



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

ब्रिक्स सम्मेलन एवं वैश्विक आर्थिक परिदृश्य: भारत के लिए अवसर और चुनौतियाँ

संजय देवांगन

(अतिथि व्याख्याता) JBS, अर्थशास्त्र विभाग, शास. जे. एम. पी. महाविद्यालय, तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) ।

सार

वर्तमान वैश्विक आर्थिक एवं भू-राजनीतिक परिदृश्य में ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच के रूप में उभरकर सामने आया है। वर्ष 2026 में भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की तथा 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत की अध्यक्षता का प्रमुख विषय "सक्षमता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास" रहा, जिसने वैश्विक दक्षिण, समावेशी विकास, आर्थिक सहयोग, प्रौद्योगिकी, जलवायु कार्रवाई तथा बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार जैसे विषयों को प्रमुखता प्रदान की। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में ब्रिक्स की बढ़ती भूमिका तथा भारत के लिए उससे उत्पन्न होने वाले आर्थिक, कूटनीतिक, तकनीकी और सामरिक अवसरों एवं चुनौतियों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में पूर्णतः द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रिक्स के आधिकारिक दस्तावेजों, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों एवं शोध-सामग्रियों को अध्ययन के प्रमुख स्रोत के रूप में लिया गया है। अध्ययन में विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के हितों की अभिव्यक्ति, व्यापार एवं निवेश, स्थानीय मुद्राओं में लेन-देन, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद एवं आतंकवादी वित्तपोषण तथा वैश्विक आर्थिक शासन में सुधार जैसे विषयों का विश्लेषण किया गया है। भारत के लिए ब्रिक्स एक ऐसा मंच प्रस्तुत करता है जिसके माध्यम से वह विकासशील देशों के हितों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। 2026 की नई दिल्ली घोषणा में वैश्विक आर्थिक शासन में विकासशील एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण भूमिका, सतत विकास तथा बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार पर बल दिया गया।

ब्रिक्स भारत के समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है। चीन का आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव, भारत-चीन सीमा विवाद, आतंकवाद के प्रश्न पर सदस्य देशों के बीच मतभेद, रूस के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक संबंधों के संदर्भ में अमेरिकी व्यापारिक नीतियाँ तथा वैश्विक संरक्षणवाद ऐसी प्रमुख चुनौतियाँ हैं जिनका भारत को संतुलित कूटनीति के माध्यम से सामना करना होगा। ब्रिक्स भारत के लिए अवसरों का महत्वपूर्ण मंच है, किंतु इसके प्रभावी उपयोग के लिए आर्थिक क्षमता, कूटनीतिक संतुलन, तकनीकी आत्मनिर्भरता तथा बहुपक्षीय सहयोग को समान रूप से सुदृढ़ करना आवश्यक है।

प्रमुख शब्द: ब्रिक्स, भारत, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक दक्षिण, आर्थिक सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, अवसर एवं चुनौतियाँ।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

1. प्रस्तावना

विगत दो दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं भू-राजनीति की संरचना में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। विश्व अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे एकध्रुवीय संरचना से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती आर्थिक शक्ति, वैश्विक व्यापार में विकासशील देशों की भूमिका, प्रौद्योगिकी का तीव्र विस्तार तथा वैश्विक आर्थिक शासन में प्रतिनिधित्व की मांग ने बहुपक्षीय मंचों के महत्व को बढ़ाया है।

इसी परिवर्तित वैश्विक व्यवस्था में ब्रिक्स का उदय एक महत्वपूर्ण घटना है। ब्रिक्स की अवधारणा ब्राजील, रूस, भारत और चीन के संदर्भ में विकसित हुई तथा दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के पश्चात इसका नाम ब्रिक्स हुआ। वर्ष 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के शामिल होने तथा वर्ष 2025 में इंडोनेशिया के पूर्ण सदस्य बनने से इसका विस्तार हुआ।

वर्ष 2026 भारत के लिए ब्रिक्स के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। भारत ने वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की और नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन का विषय "सक्षमता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास" रहा। यह विषय भारत की उन प्राथमिकताओं को अभिव्यक्त करता है जिनमें वैश्विक दक्षिण की आवाज को सशक्त करना, आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग बढ़ाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा सतत विकास को गति देना शामिल है।

ब्रिक्स का महत्व केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है। यह राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, वित्तीय, सांस्कृतिक तथा जन-से-जन संपर्क जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का मंच बन चुका है। नई दिल्ली घोषणा में भी ब्रिक्स सहयोग के तीन प्रमुख स्तंभों—राजनीतिक एवं सुरक्षा, आर्थिक एवं वित्तीय तथा सांस्कृतिक एवं जन-से-जन सहयोग—को रेखांकित किया गया है।

आतंकवाद भारत के लिए लंबे समय से एक महत्वपूर्ण सुरक्षा एवं आर्थिक चुनौती रहा है। आतंकवाद न केवल किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता है, बल्कि निवेश, पर्यटन, व्यापार, अवसंरचना तथा आर्थिक स्थिरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए भारत अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मंचों पर आतंकवाद तथा आतंकवादी वित्तपोषण के विरुद्ध सामूहिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को निरंतर रेखांकित करता रहा है।

वर्तमान समय में संरक्षणवाद, व्यापारिक प्रतिबंध, शुल्क-नीतियाँ, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान तथा भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिक्स भारत को विकासशील देशों के साथ आर्थिक एवं कूटनीतिक सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। भारत एक बड़ी और तेजी से विस्तार करती अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल भुगतान, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता ब्रिक्स सहयोग को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। यह अध्ययन इस मूल प्रश्न पर केंद्रित है कि ब्रिक्स भारत की आर्थिक एवं कूटनीतिक क्षमता को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है और इस प्रक्रिया में भारत को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

2. साहित्य समीक्षा

ब्रिक्स से संबंधित उपलब्ध साहित्य में इसके आर्थिक विस्तार, वैश्विक शासन में भूमिका, वैश्विक दक्षिण के हितों, वित्तीय संस्थागत निर्माण, भारत-चीन संबंध, ऊर्जा सहयोग, सुरक्षा सहयोग तथा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में संभावित परिवर्तन जैसे विभिन्न आयामों का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए वर्ष 2020 से 2025 के बीच प्रकाशित प्रमुख शोध अध्ययनों का चयन किया गया है, ताकि वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में ब्रिक्स की भूमिका को अधिक समकालीन दृष्टिकोण से समझा जा सके।

कूपर (2021) ने चीन और भारत के जी20 तथा ब्रिक्स में सहभागिता का तुलनात्मक अध्ययन किया। उनके अध्ययन के अनुसार चीन और भारत दोनों स्वयं को उभरती हुई शक्तियों के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ वैश्विक दक्षिण के हितों के प्रतिनिधि के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत की ब्रिक्स नीति में वैश्विक नेतृत्व और विकासशील देशों के साथ एकजुटता दोनों तत्व विद्यमान हैं।

फ्राकालोसी डी मोराएस (2020) ने ब्रिक्स में सुरक्षा सहयोग का अध्ययन करते हुए यह पाया कि सदस्य देशों के बीच संप्रभुता और राज्य-केंद्रित व्यवस्था जैसे सिद्धांत सहयोग के लिए आधार प्रदान करते हैं। हालांकि, घरेलू राजनीतिक परिस्थितियाँ तथा सदस्य देशों के अलग-अलग हित सुरक्षा सहयोग की गहराई को प्रभावित करते हैं। यह अध्ययन भारत द्वारा आतंकवाद एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों को ब्रिक्स मंच पर उठाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

पापा (2021) ने भारत-चीन संघर्ष के संदर्भ में ब्रिक्स के भविष्य का विश्लेषण किया। अध्ययन में बताया गया कि भारत और चीन के बीच तनाव के बावजूद ब्रिक्स की संस्थागत संरचना पूरी तरह कमजोर नहीं हुई। हालांकि, भारत-चीन संबंधों में तनाव संगठन के दीर्घकालिक सहयोग और सामूहिक नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। यह निष्कर्ष प्रस्तुत शोध में भारत-चीन सीमा विवाद को प्रमुख चुनौती के रूप में शामिल करने के आधार को मजबूत करता है।

लुओ (2021) ने ब्रिक्स की बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, विशेष रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था, में समानता एवं समता के सिद्धांतों का अध्ययन किया। अध्ययन के अनुसार ब्रिक्स संस्थाओं में पारंपरिक ब्रेटन वुड्स संस्थाओं की तुलना में समान भागीदारी और सर्वसम्मति पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है। यह भारत के लिए वैकल्पिक विकास-वित्त व्यवस्था की संभावनाओं को समझने में उपयोगी है।

हूइजमाइजर्स (2022) ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से ब्रिक्स के आंतरिक एवं बाह्य संस्थागतकरण का अध्ययन किया। उनके अनुसार न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स सहयोग को केवल वार्षिक शिखर सम्मेलनों तक सीमित न रखते हुए उसे संस्थागत स्वरूप प्रदान करने में योगदान दिया है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि बैंक अभी विकासशील अवस्था में है और इसकी भविष्य की प्रभावशीलता इसके संस्थागत विस्तार तथा सदस्य देशों के सहयोग पर निर्भर करेगी।

डगन, लाडिनेस अज़ालिया एवं रेविज़ोस्की (2022) ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में ब्रिक्स की संरचनात्मक शक्ति का अध्ययन किया। उनके अध्ययन में यह निष्कर्ष सामने आया कि न्यू डेवलपमेंट



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

बैंक ब्रिक्स को वैकल्पिक विकास-वित्त का माध्यम प्रदान करता है, किंतु अभी तक यह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के मूल नियमों एवं मानदंडों को व्यापक रूप से परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त संरचनात्मक शक्ति प्राप्त नहीं कर पाया है। यह निष्कर्ष ब्रिक्स की संभावनाओं और सीमाओं दोनों को समझने में महत्वपूर्ण है।

लियू एवं पापा (2022) ने ब्रिक्स द्वारा वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के संभावित डी-डॉलरकरण का अध्ययन किया। उन्होंने ब्रिक्स देशों द्वारा स्थानीय मुद्राओं में लेन-देन, वित्तीय सहयोग तथा वैकल्पिक वित्तीय तंत्रों के विकास को डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में विश्लेषित किया। यह अध्ययन प्रस्तुत शोध में स्थानीय मुद्रा, वित्तीय सहयोग और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था से संबंधित विश्लेषण के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।

पापा, हान एवं ओ'डॉनेल (2023) ने ब्रिक्स की अनौपचारिक संस्थाओं एवं प्रतिहेजेमोनिक क्षमता का अध्ययन करते हुए ब्रिक्स अभिसरण सूचकांक की अवधारणा प्रस्तुत की। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह समझना था कि विभिन्न राष्ट्रीय हितों के बावजूद सदस्य देश किन क्षेत्रों में नीतिगत अभिसरण विकसित करते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि ब्रिक्स की शक्ति केवल औपचारिक संस्थाओं में नहीं, बल्कि सदस्य देशों के बीच निरंतर नीति-समन्वय में भी निहित है।

हान एवं पापा (2024) ने ब्रिक्स में नेतृत्व और प्रदर्शन की आंतरिक गतिशीलता का अध्ययन किया। उनके अध्ययन ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि ब्रिक्स जैसे अनौपचारिक बहुपक्षीय संगठन में नेतृत्व किस प्रकार विकसित होता है और सदस्य देशों के बीच शक्ति एवं प्राथमिकताओं का संबंध संगठन की कार्यक्षमता को किस प्रकार प्रभावित करता है। यह अध्ययन भारत की अध्यक्षता तथा संगठन के भीतर नेतृत्वकारी भूमिका के विश्लेषण के लिए उपयोगी आधार प्रदान करता है।

पापा एवं हान (2025) ने ब्रिक्स में अनौपचारिक संस्थाओं तथा सॉफ्ट बैलेंसिंग के विकास का अध्ययन किया। उनके शोध से यह समझने में सहायता मिलती है कि ब्रिक्स सदस्य देश मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को सीधे चुनौती देने के बजाय संस्थागत सहयोग, नीतिगत समन्वय और सामूहिक मंचों के माध्यम से अपनी भूमिका को कैसे विस्तृत करते हैं। यह दृष्टिकोण भारत की बहुध्रुवीय एवं संतुलित विदेश नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

उपरोक्त साहित्य से स्पष्ट होता है कि ब्रिक्स को केवल उभरती अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक समूह के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। उपलब्ध शोध में इसे वैश्विक शासन, वैकल्पिक वित्तीय संस्थाओं, वैश्विक दक्षिण, सुरक्षा सहयोग, ऊर्जा, वित्तीय व्यवस्था तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था से जोड़कर देखा गया है। साथ ही, साहित्य यह भी इंगित करता है कि भारत-चीन संबंध, सदस्य देशों के अलग-अलग राष्ट्रीय हित, नेतृत्व संबंधी प्रश्न तथा संस्थागत सीमाएँ ब्रिक्स की सामूहिक प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती हैं।

पूर्ववर्ती अध्ययनों ने ब्रिक्स की संस्थागत संरचना, वित्तीय सहयोग, वैश्विक शासन तथा सदस्य देशों के रणनीतिक संबंधों का अलग-अलग अध्ययन किया है। किंतु भारत की वर्ष 2026 की अध्यक्षता को केंद्र में रखते हुए आर्थिक अवसर, वैश्विक दक्षिण, आतंकवाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, सतत विकास तथा भारत के समक्ष उपस्थित आर्थिक एवं भू-राजनीतिक चुनौतियों को एक



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

समेकित ढाँचे में विश्लेषित करने की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। प्रस्तुत शोध-पत्र इसी शोध-अंतर को संबोधित करने का प्रयास करता है।

3. शोध कार्यप्रणाली

प्रस्तुत शोध-पत्र वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है।

3.1 आंकड़ों के स्रोत

अध्ययन में पूर्णतः द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं:

1. विश्व बैंक
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
3. ब्रिक्स के आधिकारिक दस्तावेज
4. न्यू डेवलपमेंट बैंक
5. भारत सरकार एवं विदेश मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेज
6. प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समाचार-पत्र
7. आर्थिक एवं शोध पत्रिकाएँ
8. उपलब्ध शोध-पत्र एवं विश्लेषणात्मक रिपोर्टें

3.2 आंकड़ों का संकलन

अध्ययन से संबंधित आर्थिक, व्यापारिक, ऊर्जा, तकनीकी एवं कूटनीतिक सूचनाओं को विभिन्न आधिकारिक तथा विश्वसनीय द्वितीयक स्रोतों से संकलित किया गया।

3.3 विश्लेषण की पद्धति

प्राप्त आंकड़ों को सारणीबद्ध एवं तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करते हुए गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार का विश्लेषण किया गया है। इसके माध्यम से भारत की आर्थिक स्थिति, ब्रिक्स की वैश्विक भूमिका तथा भारत के समक्ष उपलब्ध अवसरों एवं चुनौतियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

4. शोध के उद्देश्य एवं परिकल्पनाएँ

4.1 शोध के उद्देश्य

1. ब्रिक्स की 2026 की भारतीय अध्यक्षता के संदर्भ में भारत के लिए उपलब्ध आर्थिक एवं रणनीतिक अवसरों का विश्लेषण करना।
2. यह अध्ययन करना कि ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण के आर्थिक एवं राजनीतिक हितों को वैश्विक स्तर पर किस प्रकार प्रभावी अभिव्यक्ति प्रदान कर सकता है।
3. आतंकवाद एवं आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम के संदर्भ में ब्रिक्स मंच की उपयोगिता का अध्ययन करना।
4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत विकास से संबंधित ब्रिक्स की पहलों का विश्लेषण करना।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

5. भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों, जैसे भारत-चीन सीमा विवाद, आतंकवाद, वैश्विक संरक्षणवाद, व्यापारिक शुल्क-नीतियाँ तथा खाद्य एवं कृषि नीति से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करना।

4.2 शोध की परिकल्पनाएँ

शून्य परिकल्पना (H_0): ब्रिक्स भारत के लिए कोई महत्वपूर्ण आर्थिक एवं रणनीतिक अवसर प्रदान नहीं करता तथा वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका सीमित है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1): ब्रिक्स भारत के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक एवं रणनीतिक अवसर प्रदान करता है तथा आतंकवाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास जैसे विषयों पर वैश्विक सहयोग एवं नीति-निर्माण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

5. मुख्य भाग एवं आंकड़ा विश्लेषण

5.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स की स्थिति

ब्रिक्स के विस्तार के साथ इसका वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक महत्व बढ़ा है। सदस्य देशों की बड़ी जनसंख्या, विशाल बाजार, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा क्षमता तथा उत्पादन एवं व्यापारिक क्षमता इसे वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है।

ब्रिक्स का बढ़ता आर्थिक आकार विकासशील देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में अपनी सामूहिक आवाज मजबूत करने का अवसर देता है। नई दिल्ली घोषणा में भी उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक आर्थिक शासन में अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण भूमिका तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

इस संदर्भ में भारत के लिए ब्रिक्स की उपयोगिता केवल व्यापारिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वित्तीय सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग, निवेश, अवसंरचना विकास तथा वैश्विक आर्थिक नीतियों के निर्माण में भागीदारी से भी संबंधित है।

5.2 ब्रिक्स देशों की आर्थिक स्थिति एवं भारत की भागीदारी

ब्रिक्स देशों की सकल घरेलू उत्पाद संबंधी तुलना से स्पष्ट होता है कि चीन का आर्थिक आकार समूह के भीतर अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जबकि भारत भी एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत की बढ़ती सकल घरेलू उत्पाद क्षमता उसके विस्तृत घरेलू बाजार, युवा कार्यबल, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षमता तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार से जुड़ी हुई है।

भारत की आर्थिक क्षमता में वृद्धि उसके लिए ब्रिक्स के माध्यम से व्यापार, निवेश एवं तकनीकी सहयोग के नए अवसर पैदा करती है। यदि भारत अपनी उत्पादन क्षमता, कौशल विकास, रोजगार सृजन तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करता है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव वास्तविक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

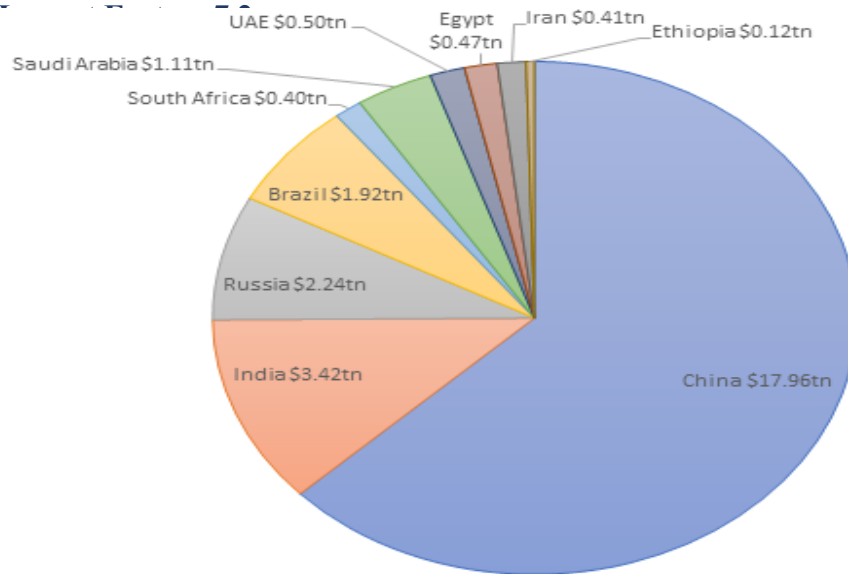
भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न पहलें—जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एक जिला-एक उत्पाद तथा उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना—उत्पादन एवं रोजगार क्षमता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

No: 3049-4176



भारत की विशाल युवा आबादी को यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल एवं आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है, तो यह जनसंख्या मानव पूंजी में परिवर्तित हो सकती है। इससे उत्पादकता, रोजगार तथा आर्थिक विकास को गति मिल सकती है।

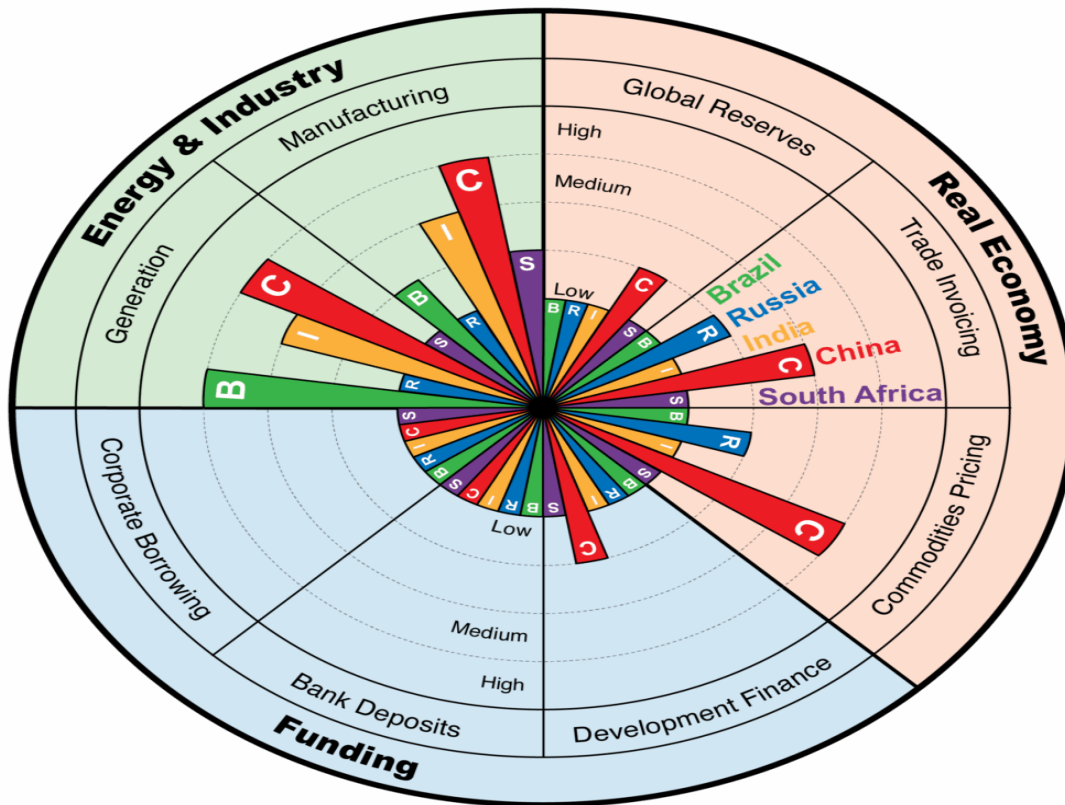
ब्रिक्स देशों की वैश्विक स्थिति और भारत की भागीदारी को समझने के लिए निम्नलिखित आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण आवश्यक है:

Expanded BRICS GDP in trillions of USD; Source: World Bank

ब्रिक्स देशों की जीडीपी की बात करें तो चीन के बाद भारत की जो भूमिका है काफी महत्वपूर्ण है। जिसमें उपर्युक्त आंकड़ों के अनुसार चीन की GDP \$ 17.96 Tn तो दूसरे स्थान पर भारत की GDP \$ 3.42 Tn हैं। भारत के बढ़ते GDP से अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में पैर पसार रहा है जो भारत की आर्थिक स्थिति को काफी महत्वपूर्ण ढंग से दिखाता है। भविष्य में भारत के लिए एक अवसर का सृजन भी करता है जो भारत की विशाल आबादी के लिए एक रणनीतिक भूमिका को दिखाता है।

यदि हम इन क्षेत्रों में सही ढंग से काम करते हैं तो भविष्य में भारत की स्थिति काफी बेहतर हो सकती है। भारत के सामने आज जो बड़ी चुनौतियाँ हैं जैसे आर्थिक समस्या और बेरोजगारी की समस्या, वे काफी हद तक दूर हो सकती हैं।

बेरोजगारी की समस्या दूर होने से देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इससे हमारे देश के कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र - इन तीनों को काफी बढ़ावा मिलेगा।



उत्पादन में वृद्धि होने से रोजगार के नए अवसर बनेंगे और बेरोजगारी की समस्या का हल होगा। परिणामस्वरूप देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक - इन सभी स्थितियों में काफी सुधार देखने को मिलेगा।

(ज़ोंगयुआन ज़ोई लियू और मिहेला पापा, 2022, "क्या BRICS ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को डी-डॉलराइज़ कर सकता है" से लिया गया।)

रियल इकोनॉमी (BRICS देशों की तुलना में) में अगर हम अपने देश की स्थिति देखें तो वह काफी गंभीर स्थिति में है। BRICS देशों में चीन और रूस के बाद भारत की स्थिति काफी दयनीय स्थिति में है। यदि हम इसी स्थिति को सुधारेंगे तो भारत सरकार की कई सारी योजनाएँ हैं जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एक जिला-एक उत्पाद और PLI स्कीम आदि।

कृषि क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र और स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI तकनीक जैसी कई नई तकनीकें हैं। इन सब तकनीकी सुविधाओं को बढ़ावा देकर और सरकार की सभी योजनाओं को बढ़ावा देकर हम अपनी रियल इकोनॉमी की स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

इसके साथ-साथ वैश्विक आर्थिक स्थिति में भारत अपना वर्चस्व स्थापित करेगा और अपना परचम लहराएगा। यदि हम भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार करते हैं तो भारत में जो विशाल युवा आबादी है, उसको मानव संसाधन के रूप में विकसित करेंगे तो भविष्य में भारत की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित हो सकता है।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

फंडिंग की स्थिति भी हमारे देश की काफी दयनीय है। यदि हम उपयुक्त क्षेत्रों में सुधार करते हैं और बदलाव लाते हैं तो उससे हमारे देश की फंडिंग की स्थिति भी काफी सुव्यवस्थित और उसमें सुधार होगा। ऊर्जा और उद्योग के क्षेत्र में विश्व के देशों की तुलना में चीन और रूस के बाद भारत की स्थिति थोड़ी अच्छी है। लेकिन हमारे यहाँ की ऊर्जा ज्यादातर परंपरागत ऊर्जा पर आधारित है, जो भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाता है।

साथ ही हमारे देश का 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है, उसे हासिल करना भी एक चुनौती है। क्योंकि अभी भारत का अधिकांश सेक्टर पूरी तरह से परंपरागत ऊर्जा पर निर्भर हैं। लेकिन हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा के भी कई विकल्प हैं, जैसे सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा और कई अन्य वैकल्पिक ऊर्जाएँ, जो भारत के लिए अवसर उपलब्ध करा रही हैं।

इस दिशा में भारत सरकार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जैसे कई संगठनों के साथ मिलकर वैकल्पिक और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

ऊर्जा या विद्युत की आपूर्ति उद्योगों के लिए भी जरूरी है और हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र, घरेलू उपभोक्ता, कृषि और अन्य क्षेत्र ज्यादातर परंपरागत ऊर्जा पर आधारित है, जो कहीं न कहीं भारत के लिए चुनौती साबित हो सकता है। यदि हम इस क्षेत्र में सुधार करते हैं और परंपरागत ऊर्जा से वैकल्पिक या स्वच्छ ऊर्जा पर स्थानांतरित होते हैं, तो हमारे देश के ऊर्जा संसाधनों में काफी सुधार होगा और भविष्य में 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को भी हम हासिल करने में सफल हो सकते हैं। सरकार की योजनाएँ जैसे PM सूर्य घर योजना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

वर्तमान परिदृश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आर्थिक उत्पादकता का नया इंजन है। भारत ने ब्रिक्स कार्यसमूहों में एआई के नैतिक उपयोग (Ethical AI) और साइबर सुरक्षा पर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए 'लाइफ' (LiFE - Lifestyle for Environment) आंदोलन को ब्रिक्स के क्लाइमेट एक्शन एजेंडे में शामिल कराना भारत

5.3 भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था एवं रोजगार की चुनौती

भारत की आर्थिक प्रगति के बावजूद रोजगार सृजन, उत्पादकता वृद्धि, कौशल असमानता तथा क्षेत्रीय आर्थिक विषमता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कृषि, उद्योग एवं सेवा—तीनों क्षेत्रों में तकनीकी नवाचार एवं निवेश को बढ़ावा देना आवश्यक है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, डिजिटल सेवाएँ तथा उन्नत विनिर्माण तकनीकें उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर सकती हैं। कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मौसम पूर्वानुमान, फसल प्रबंधन, बाजार सूचना तथा संसाधन अनुकूलन जैसी तकनीकों का उपयोग कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

इसी प्रकार शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार की संभावनाएँ उत्पन्न होती हैं।

5.4 ऊर्जा एवं स्वच्छ ऊर्जा: भारत के लिए अवसर और चुनौती

भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। औद्योगिक उत्पादन, कृषि, परिवहन, घरेलू उपभोग तथा सेवा क्षेत्र सभी पर्याप्त एवं विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर हैं।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

भारत की एक प्रमुख चुनौती पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता तथा ऊर्जा संक्रमण की गति से संबंधित है। भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा दक्षता तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ाना आवश्यक होगा।

भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सूर्य घर जैसी योजनाएँ घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा के विस्तार में योगदान दे सकती हैं।

ब्रिक्स के माध्यम से भारत को ऊर्जा प्रौद्योगिकी, जलवायु वित्त, हरित निवेश तथा स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सदस्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है।

5.5 कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल अर्थव्यवस्था

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पादकता, नवाचार तथा प्रतिस्पर्धात्मकता का एक महत्वपूर्ण आधार बनती जा रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, उद्योग, परिवहन, प्रशासन तथा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है।

भारत के लिए ब्रिक्स के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार एवं नैतिक उपयोग, डिजिटल शासन, साइबर सुरक्षा तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण संभावनाएँ हैं।

वर्ष 2025 में ब्रिक्स स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक शासन से संबंधित संयुक्त पहल को महत्व दिया गया था और वर्ष 2026 में भी तकनीकी एवं नवाचार सहयोग को भारतीय अध्यक्षता के व्यापक एजेंडे में स्थान मिला।

भारत यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आर्थिक विकास, कौशल निर्माण एवं सार्वजनिक सेवा वितरण के साथ प्रभावी रूप से जोड़ता है, तो यह भविष्य की अर्थव्यवस्था में उसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

5.6 सतत विकास एवं जलवायु कार्रवाई

ब्रिक्स के समक्ष उपस्थित प्रमुख विषयों में सतत विकास भी शामिल है। वैश्विक दक्षिण के अनेक देशों के लिए आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ जल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता तथा जलवायु कार्रवाई जैसे विषयों पर सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

भारत ने पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली की अवधारणा के माध्यम से जलवायु कार्रवाई को सामाजिक व्यवहार एवं विकास नीति से जोड़ने का प्रयास किया है। ब्रिक्स सहयोग की पहलों के अनुभव-साझाकरण एवं विस्तार के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान कर सकता है।

नई दिल्ली घोषणा में 2030 एजेंडा, असमानता में कमी तथा सतत विकास से संबंधित सहयोग को विशेष महत्व दिया गया है।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

5.7 वैश्विक दक्षिण और भारत की भूमिका

ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण आयाम वैश्विक दक्षिण की आवाज को अधिक प्रभावी बनाना है। विकासशील एवं उभरती अर्थव्यवस्थाएँ वैश्विक उत्पादन एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, किंतु अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एवं निर्णयकारी संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी उनकी आर्थिक भूमिका के अनुरूप नहीं माना जाता।

नई दिल्ली घोषणा में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा वैश्विक आर्थिक शासन में उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की आवाज एवं प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर है। भारत ब्रिक्स के माध्यम से विकासशील देशों की आवश्यकताओं को वैश्विक आर्थिक विमर्श में अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है।

5.8 आतंकवाद एवं आतंकवादी वित्तपोषण

आतंकवाद भारत की सुरक्षा एवं विकास संबंधी चिंताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आतंकवादी गतिविधियाँ प्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन एवं सुरक्षा को प्रभावित करने के साथ-साथ निवेश, पर्यटन, व्यापार तथा आर्थिक स्थिरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

भारत ब्रिक्स के माध्यम से आतंकवाद तथा आतंकवादी वित्तपोषण के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर सकता है। हालांकि इस विषय पर सदस्य देशों की सुरक्षा प्राथमिकताओं एवं राजनीतिक दृष्टिकोण में अंतर मौजूद हो सकता है।

इसलिए भारत के लिए आवश्यक है कि वह व्यापक सहमति, प्रमाण-आधारित सहयोग तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी बहुपक्षीय तंत्र विकसित करने की दिशा में कार्य करे।

6. भारत के लिए ब्रिक्स से उत्पन्न प्रमुख अवसर

भारत के लिए ब्रिक्स निम्नलिखित प्रमुख अवसर प्रस्तुत करता है:

6.1 व्यापार एवं निवेश विस्तार

ब्रिक्स के विस्तारित बाजार भारत के निर्यातकों, निवेशकों तथा उद्योगों के लिए नए अवसर उपलब्ध करा सकते हैं।

6.2 स्थानीय मुद्राओं में व्यापार

स्थानीय मुद्राओं में व्यापार एवं भुगतान तंत्र के विकास से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिम को कुछ हद तक कम करने की संभावनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

6.3 न्यू डेवलपमेंट बैंक

न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से अवसंरचना, सतत विकास तथा विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग की संभावनाएँ बढ़ती हैं।

6.4 तकनीकी सहयोग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शासन, साइबर सुरक्षा, जैव-प्रौद्योगिकी तथा हरित तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग भारत के लिए उपयोगी हो सकता है।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

6.5 ऊर्जा सुरक्षा

ब्रिक्स देशों के बीच ऊर्जा सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक हो सकता है।

6.6 वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व

भारत विकासशील देशों की आर्थिक एवं विकास संबंधी प्राथमिकताओं को वैश्विक मंच पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है।

7. भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

7.1 चीन का बढ़ता आर्थिक प्रभाव

ब्रिक्स के भीतर चीन का विशाल आर्थिक आकार भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक तथ्य है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्रिक्स की संस्थागत एवं आर्थिक दिशा किसी एक सदस्य की प्राथमिकताओं तक सीमित न हो।

7.2 भारत-चीन सीमा विवाद

भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी विवाद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करता है। यह परिस्थिति ब्रिक्स के भीतर आर्थिक सहयोग और व्यापक रणनीतिक संबंधों के बीच संतुलन की आवश्यकता को बढ़ाती है।

7.3 आतंकवाद पर मतभेद

आतंकवाद की परिभाषा, सुरक्षा प्राथमिकताओं तथा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सदस्य देशों के दृष्टिकोण में अंतर होने के कारण सर्वसम्मति प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

7.4 अमेरिकी व्यापारिक नीतियाँ

भारत के रूस के साथ ऊर्जा एवं व्यापारिक संबंधों तथा ब्रिक्स के साथ उसके बढ़ते सहयोग के संदर्भ में अमेरिकी व्यापारिक एवं शुल्क संबंधी नीतियाँ भारत के लिए आर्थिक एवं कूटनीतिक चुनौती उत्पन्न कर सकती हैं।

भारत के लिए आवश्यक है कि वह ब्रिक्स के साथ सहयोग को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य प्रमुख आर्थिक साझेदारों के साथ अपने संबंधों में भी संतुलन बनाए रखे।

7.5 सदस्य देशों के हितों में विविधता

ब्रिक्स के सदस्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएँ, आर्थिक संरचनाएँ, विकास स्तर और विदेश नीति संबंधी प्राथमिकताएँ एक-दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए सभी विषयों पर समान दृष्टिकोण विकसित करना सरल नहीं है।

8. विचार-विमर्श

प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिक्स वर्तमान वैश्विक आर्थिक एवं भू-राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच के रूप में विकसित हुआ है। ब्रिक्स का विस्तार तथा सदस्य देशों की बढ़ती आर्थिक क्षमता इसे वैश्विक आर्थिक शासन, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और सतत विकास से संबंधित विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। भारत के लिए ब्रिक्स केवल आर्थिक



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

सहयोग का मंच नहीं है, बल्कि वैश्विक दक्षिण के हितों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में इस मंच का महत्व और अधिक बढ़ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आर्थिक सहयोग, सतत विकास, नवाचार, प्रौद्योगिकी, जलवायु कार्रवाई तथा वैश्विक शासन में सुधार जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई। इससे भारत को अपनी विकास प्राथमिकताओं को व्यापक वैश्विक विमर्श से जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ।

आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रिक्स भारत के लिए व्यापार एवं निवेश के विस्तार की संभावनाएँ प्रस्तुत करता है। ब्रिक्स के विस्तारित बाजारों में भारतीय वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए नए अवसर विकसित हो सकते हैं। इसी प्रकार स्थानीय मुद्राओं में व्यापार तथा वैकल्पिक भुगतान व्यवस्थाओं पर सहयोग बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुछ परिस्थितियों में विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिमों को कम करने की संभावनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि, ऐसी व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों, वित्तीय प्रणालियों और आपसी सहमति पर निर्भर करेगी।

न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से अवसंरचना तथा सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग की संभावनाएँ भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत जैसे विशाल विकासशील देश के लिए परिवहन, ऊर्जा, शहरी अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल अवसंरचना में दीर्घकालिक निवेश आर्थिक विकास को गति देने में सहायक हो सकता है।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, वित्तीय सेवाओं तथा सार्वजनिक प्रशासन में उत्पादकता एवं सेवा-प्रदाय में सुधार के लिए किया जा सकता है। ब्रिक्स के माध्यम से भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार उपयोग, साइबर सुरक्षा, डिजिटल शासन तथा तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा दे सकता है।

ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भी ब्रिक्स सहयोग महत्वपूर्ण है। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण दोनों समान रूप से आवश्यक हैं। सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सहयोग भारत के दीर्घकालिक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में उपयोगी हो सकता है। इसके साथ ही विकासशील देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं और जलवायु संबंधी दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करना भी आवश्यक है।

वैश्विक दक्षिण के संदर्भ में ब्रिक्स की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विकासशील देशों की आर्थिक आवश्यकताएँ विकसित देशों से भिन्न हो सकती हैं। वित्त, प्रौद्योगिकी, जलवायु संसाधन, व्यापार तथा विकास वित्तपोषण जैसे क्षेत्रों में विकासशील देशों की आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने में ब्रिक्स उपयोगी मंच बन सकता है। भारत इस प्रक्रिया में मध्यस्थ एवं समन्वयकारी भूमिका निभाने का प्रयास कर सकता है।

ब्रिक्स के समक्ष अनेक संरचनात्मक चुनौतियाँ भी हैं। सदस्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं, आर्थिक हितों तथा विदेश नीति संबंधी प्राथमिकताओं में पर्याप्त विविधता है। विशेष रूप से चीन का विशाल



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

आर्थिक आकार तथा भारत-चीन के बीच विद्यमान सीमा विवाद दोनों देशों के संबंधों को जटिल बनाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भारत को आर्थिक सहयोग और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा।

आतंकवाद एवं आतंकवादी वित्तपोषण का विषय भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स मंच के माध्यम से आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने का प्रयास कर सकता है। किंतु सदस्य देशों के बीच सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोणों में अंतर होने के कारण व्यापक सहमति बनाना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है।

इसी प्रकार वैश्विक संरक्षणवाद, व्यापारिक शुल्क तथा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की बदलती व्यापार नीतियाँ भारत के लिए अतिरिक्त चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती हैं। भारत को ब्रिक्स के साथ सहयोग बढ़ाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य प्रमुख आर्थिक साझेदारों के साथ भी अपने आर्थिक एवं कूटनीतिक संबंधों में संतुलन बनाए रखना होगा।

विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि ब्रिक्स भारत के लिए अवसरों और चुनौतियों दोनों का मंच है। इसकी वास्तविक उपयोगिता केवल घोषणाओं में नहीं, बल्कि व्यापार, निवेश, वित्त, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, जलवायु कार्रवाई तथा सतत विकास के क्षेत्र में ठोस परिणामों से निर्धारित होगी। भारत के लिए आवश्यक है कि वह अपनी आर्थिक क्षमता, तकनीकी दक्षता, मानव पूंजी और कूटनीतिक क्षमता को मजबूत करते हुए ब्रिक्स सहयोग का व्यावहारिक उपयोग करे।

, ब्रिक्स भारत को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को विस्तृत करने, वैश्विक दक्षिण के हितों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने तथा बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही, चीन के प्रभाव, सदस्य देशों के मतभेदों, वैश्विक व्यापारिक तनाव तथा भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का संतुलित एवं दूरदर्शी कूटनीतिक दृष्टिकोण से सामना करना आवश्यक होगा।

9. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ब्रिक्स भारत के लिए आर्थिक, कूटनीतिक, तकनीकी एवं रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। वर्ष 2026 में भारत की अध्यक्षता तथा नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने भारत को वैश्विक दक्षिण, सतत विकास, आर्थिक सहयोग, तकनीकी नवाचार तथा बहुपक्षीय संस्थागत सुधार से जुड़े विषयों को प्रमुखता से आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया।

भारत के लिए ब्रिक्स के प्रमुख अवसरों में व्यापार एवं निवेश विस्तार, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की संभावनाएँ, विकास वित्त, स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, जलवायु कार्रवाई तथा वैश्विक दक्षिण की आवाज को सशक्त करना शामिल हैं।

इसके साथ ही भारत के सामने चीन के आर्थिक प्रभाव, भारत-चीन सीमा विवाद, आतंकवाद के मुद्दे पर मतभेद, वैश्विक संरक्षणवाद तथा विभिन्न देशों की व्यापारिक एवं शुल्क नीतियों जैसी चुनौतियाँ भी मौजूद हैं।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

ब्रिक्स को भारत के लिए अवसर और चुनौती—दोनों के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपनी आर्थिक शक्ति, तकनीकी क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक दक्षता तथा बहुपक्षीय सहयोग को किस प्रकार एकीकृत करता है।

भारत के लिए आवश्यक है कि वह ब्रिक्स के माध्यम से वैश्विक दक्षिण के हितों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाए, साथ ही विश्व की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक एवं रणनीतिक संबंधों में संतुलन बनाए रखे। ब्रिक्स भारत की वैश्विक भूमिका को विस्तृत करने वाला महत्वपूर्ण मंच बन सकता है, बशर्ते भारत इसका उपयोग व्यावहारिक, संतुलित और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ करे।

संदर्भ सूची

1. कूपर, ए. एफ. (2021)। चीन, भारत और ब्रिक्स: उभरती शक्ति की स्थिति की खोज। थर्ड वर्ल्ड क्वार्टरली, 42(11), 2471–2489।
2. डगन, एन., लाडिनेस अज़ालिया, एच., एवं रेविज़ोस्की, एम. (2022)। बहुपक्षीय विकास वित्त में ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) की संरचनात्मक शक्ति: न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्ययन। ग्लोबल पॉलिसी, 13(4), 479–492।
3. फ्राकालोसी डी मोराएस, ए. (2020)। ब्रिक्स और सुरक्षा सहयोग: आतंकवाद-रोधी सहयोग का अध्ययन। ग्लोबल पॉलिसी, 11(5), 619–630।
4. हूइजमाइजर्स, बी. (2022)। ब्रिक्स का आंतरिक एवं बाह्य संस्थागतकरण: न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में अध्ययन। इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, 43(4), 481–497।
5. लियू, ज़ोंगयुआन ज़ोई, एवं पापा, एम. (2022)। क्या ब्रिक्स वैश्विक वित्तीय प्रणाली का डी-डॉलरकरण कर सकता है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. लुओ, जे. (2021)। ब्रिक्स की बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं में समानता एवं समता: न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था। ग्लोबल पॉलिसी, 12(5), 647–659।
7. पापा, एम. (2021)। भारत-चीन संघर्ष की छाया में ब्रिक्स का भविष्य। ग्लोबल पॉलिसी, 12(5), 660–673।
8. पापा, एम., हान, जेड., एवं ओ'डोनेल, एफ. (2023)। ब्रिक्स अभिसरण सूचकांक और अनौपचारिक संस्थागतकरण। ग्लोबल स्टडीज़ क्वार्टरली, 3(2), 1–14।
9. पापा, एम., एवं हान, जेड. (2024)। ब्रिक्स में नेतृत्व एवं कार्य-प्रदर्शन: अनौपचारिक संस्थागतकरण की गतिशीलता। इंटरनेशनल अफेयर्स, 100(4), 1–18।
10. पापा, एम., एवं हान, जेड. (2025)। ब्रिक्स में अनौपचारिक संस्थाएँ एवं सॉफ्ट बैलेंसिंग। ग्लोबल स्टडीज़ क्वार्टरली, 5(1), 1–16।